दैनिक

सुप्रीम न्यूज

हिन्दी समाचार पत्र

आर एन आई नंबर UPHIN/2010/33252

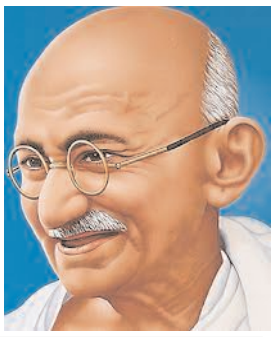

जनता का अखबार

वर्ष : 13 अंक : 294 गौतमबुद्धनगर, गुरूवार, 29 दिसम्बर 2022 उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पृष्ठ : 04 मूल्य : 05 रूपये मात्र

दरोगा का खेल मुंह मांगें पैसे नही दोगे तो जाओगे जेल

रिश्वत खोर दरोगा वारिस खान और दो सिपाही निलंबित

बदायूं। पीड़ित चंद्रपाल व उसका परिवार जनपद बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर में रहते हैं` दिनांक 27-05-2022 को पीड़ित चंद्रपाल के बच्चों में और एक मुस्लिम परिवार के बच्चों में कहा सुनी हुई और झगड़ा हो गया जिस पर चौकी इंचार्ज वारिस खान ने दिनांक 27-05-2022 को पीड़ित के बेटे अंकित का धारा 151/107/116 में चालान कर दिया। अंकित मजदूरी के साथ बी ए की भी पढ़ाई कर रहा है। पीड़ित ने अपने बेटे की जमानत करा ली`

इसके ठीक तीन दिन बाद, दिनांक 30-05-2022 को पीड़ित के बेटे अंकित पर धारा 354 क्ढउ और 452 क्ढउ में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और जाँच के नाम पर पीड़ित से रुपयों की डिमांड की गई पीड़ित से चौकी इंचार्ज वारिस खान ने 70,000/- रुपये उसे मुकदमें के नाम पर वसूल लिए जिसके लिए पीड़ित को चौकी इंचार्ज ने बताया था कि 50,000/- रुपये तो थाना प्रभारी और बड़े अधिकारियों को चले गए। मुझे तो केवल 20 हजार ही मिलें हैं। इस लिए मुझे 50 हजार रुपए और देने पड़ेंगे।

दरोगा वारिस खान को मुंह मांगें पैसे नही मिले तो गुंडा एक्ट की संतुति कर दी थी

ई-रिक्शा चला कर परिवार चलाने वाला चंद्रपाल बेहद गरीब हैं। जो ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसके बच्चे भी मजदूरी वगैरह करके अपने परिवार को चलाने में सहायता करते हैं। इसलिए पीड़ित चंद्रपाल ने चौकी इंचार्ज से रुपये देने में असमर्थता जताई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दूसरी ओर चौकी इंचार्ज वारिस खान के मुँह खून लग चुका था। जिसके चलते चौकी इंचार्ज कहाँ मानने वाला था। चौकी इंचार्ज वारिस खान ने कुछ दिन बाद ही नियमों का उल्लंघन करके सिर्फ एक ही एफआईआर पर गुंडा एक्ट की संतुति करके एडीएम बदायूं के यहाँ भेज दी गई पीड़ित को कानूनी ज्ञान न होने की वजह से पीड़ित ने एडीएम के समक्ष पेश होकर अपना जबाब दाखिल करने की वजाय मा. उच्च न्यायालय का रुख किया और मा. उच्च न्यायालय ने पीड़ित को अपना याचिका की कॉपी और मा. उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी लगाकर इंडिया पोस्ट द्वारा रजिस्ट्री की है।

पीड़ित क्या करें ? किस पर भरोसा करें ? हर कोई कानूनी अज्ञानता का लाभ उठाता है। ये मामला तो एडीएम के समक्ष ही समाप्त हो जाएगा, छोटे से मामले में पीड़ित हाईकोर्ट तक पहुंच गया फिर भी कुछ हाथ नही लगा । इस तरह के मामलों में कानून अज्ञानता के कारण पीड़ितों के साथ समस्या और भी बढ़ जाती है ~ संजय भाटी

जबाब एडीएम के समक्ष दाखिल करने के लिए कहा और सम्बंधित अथॉरिटी को आदेशित किया कि आप नियमानुसार कार्यवाही करें और पीड़ित ने प्रार्थना पत्र किसी से लिखाकर आर्डर की कॉपी के साथ एडीएम ऑफिस गया और लेकिन वहां प्रार्थना पत्र ० आर्डर लेने से मना कर दिया, तब पीड़ित ने उक्त प्रार्थना पत्र, मुकदमे के चक्कर में पीड़ित 2-3 लाख रुपये कर्जे में डूब चुका है। अब उसके पास पुलिसिया आतंकवाद से बचने के लिए आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं है।

बेलगाम दरोगा वारिस खान इतने पर भी नही रुक रहा है

जब चौकी इंचार्ज को यह पता चला तो पहले तो फैसले का दबाब बनाया लेकिन जब पीड़ित ने कहा कि हमें मा. न्यायालय पर भरोसा है तब आज चौकी इंचार्ज पीड़ित के दूसरे बेटे को धमकाकर बोला कि इस बार तुझे बंद करूँगा और जेल भेजूंगा। फिर भी बात नही बनी तो दरोगा वारिस खान ने पीड़ित को फोन करके धमकाया कि कल तक मुझे अंकित लाकर दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा` इस फर्जी

उत्तर प्रदेश में ऐसे अनगिनत मामले हो चुके हैं जब पीड़ितों ने परेशान हो होकर आत्महत्याएं की हैं। सात साल सजा तक के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने थाना स्तर पर ही मुचलके/जमानत भर कर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। फिर भी पुलिस अपनी वसूली को बरकरार रखने के लिए कोई न कोई ऐसे हथकंडे लगाती है जिससे अशिक्षित और गरीब लोगों को प्रताड़ित कर वसूली की जा सके।

बदायूं पुलिस के दरोगा वारिस खान गरीब ई-रिक्शा वाले को भी नही बक्शा आखिरकार धारा 151,107,116 से शुरू करके IPC की धारा 354,452 से गुंडा एक्ट तक में कर दी कार्यवाही। इस तरह मामले में कई पेंच है। आप भी देखें।

पीड़ित ने दरोगा वारिस खान को भी दिए थे 70 हजार। अब जब पीड़ित को पता चला है कि उसके बेटे को दरोगा वरिस खान और विपक्षियों ने मिलकर फंसा दिया है तो खुल रहे हैं दरोगा वारिस खान के भ्रष्टचार के राज, एक ई-रिक्शा वाले पिता ने अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बचाने के लिए कर्ज लेकर लाखों रुपए खर्च कर दिए। जिसमें से पीड़ित द्वारा जानकारी दी गई है कि उसने एक लाख रुपए विपक्षी को 70 हजार उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा को दे दिए। एक नजर पूरे मामले पर डालें।

दरोगा वारिस खान का यह पहला मामला नहीं है

इस मामले के साथ साथ एक और मामला सामने आया कि वारिस खान ने ग्राम लक्ष्मीपुर के ही एक आदमी को भैंस चोरी के आरोप के शक में गिरफ्तार किया और उसको थर्ड डिग्री की तालिबानी सजा दी उसके बाद सौदेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ और अन्ततः वारिस खान ने पीड़ित के परिवार से रुपये 60,000/- लेकर छोड़ा` अब पीड़ित दरोगा वारिस खान को रुपये 60,000/- की रिश्वतखोरी कराने के बाद अपना इलाज अस्पताल में करा रहा है`

पुलिसिया आतंक के एक जैसे दोनों कांड सामने आने पर बदायूँ पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ वर्मा ने दिनाँक 25-12-2022 को आनन फानन में दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित करके अपने उच्चाधिकारियों और जनता को जांच नामक झुनझुना पकड़ा दियो

बदायूँ पुलिस के आतंक की जांच बदायूँ पुलिस ही कर रही है लेकिन उनका क्या होगा जिनको दरोगा वारिस खान द्वारा लूटा गया ?

जिनको दरोगा वारिस खान द्वारा मारपीट करके प्रताड़ित किया गया ?

जिनको दरोगा वारिस खान द्वारा फर्जी मुकदमों में फंसाया गया ?

SHO और CO पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

सारे झूठे और फर्जी मुकदमों में SHO और CO ने भी हस्ताक्षर किये ही होंगे तो इनको दरोगा वारिस खान का आतंक क्यों नहीं दिखा या फिर वारिस खान की रिश्वतखोरी में SHO और CO की भी भागीदारी थी ?

हिन्द की जमीन के संपादक इसहाक सैफी को अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच का प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया

नोएडा। अखिल भारतीय पस मांदा मुस्लिम मंच के कार्य को गति प्रदान करने में इसहाक सैफी को प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व प्रदान किया गया। मंच के द्वारा कहा गया कि आप से उम्मीद की जाती है कि अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के संगठन को मजबूत एवं प्रभावी बनाने के लिए कार्य करेंगे। पसमांदा मुस्लिम समाज की सेवा का प्रयास को साकार करने में अपना योगदान देंगे एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक के हाथों को मजबूत करेंगे .

संपादकीयः-

मुख्यमंत्री ने मकान देने के नाम पर पत्रकारों के सामने टुकड़े फेंक दिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब पत्रकारों के सामने सस्ते दामों में मकान देने के नाम पर नए टुकड़े फेंक दिए हैं। पत्रकारिता को मुठ्ठी में रखने के लिए पहले से ही सरकारों ने मीडिया संस्थानों के मालिकों और पत्रकारों को तमाम तरह की नीतियों से जकड़ रखा था। कुछेक को कानूनों से तो कुछेक को सुविधाओं से जकड़ रखा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब पत्रकारों के सामने सस्ते दामों में मकान देने के नाम पर नए टुकड़े फेंक दिए हैं। इस सब में जन हितैषी पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। टुकड़खोर गर्दन झुकाकर पुंछ हिलाते हुए वफादारी साबित करने की होड़ और वफादारी के नशे में गुर्रा-गुर्रा कर जनता को लहूलुहान कर देंगे। कुछेक तो हमारे जैसों के घरों पर बुलडोजरों को लेकर पहुंच जाएंगे। अच्छे से समझ लीजिए बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे परिवेश में सरकारी सुविधाओं के साथ सम्मान का ये तोहफा अब जनहितैषी पत्रकारिता को जड़ से खत्म कर देगा। वह दिन दूर नहीं है जब गली मोहल्ले की पत्रकारिता कर रहे पत्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा लठिया कर खदेड़ दिए जाएंगे। यदि लठिया कर दौड़ाए जाने से भी नही माने

तो जबरन पकड़ पकड़ कर जेलों में ठूंस दिए जाएंगे। इतने भर से पीछा नही छूटेगा। जमानत तक नही होंगी। यदि पत्रकारों के यारे प्यारे सरकार द्वारा खदेड़े गए पत्रकारों की जमानत करवाएंगे तो ऐसे लोगों पर भी सरकार के लठहत और बुलडोजर तक की तमाम योजनाएं उनका पीछा करती दिखाई देंगी। इस सब की कवरेज के लिए मान्यता प्राप्त पत्रकार सरकारी आवास योजनाओं की लालसा में पूरी तन्मयता और आकाओं की वफादारी के साथ कर अपनी सरकारी आवासीय योजना की पात्रता की दावेदारी करेंगे। अभी तक छोटे मोटे अखबारों व पत्रिकाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पत्रकारिता करके धुरंधर बने फिर रहे पत्रकारों की समझ में यह बात नही आ रही है। क्योंकि सभी अपने आप में यह सोचकर चल रहे हैं कि एक दिन वह फलां प्रेस क्लब या फलां पत्रकार संगठन के अध्यक्ष बन जाएंगे। सभी की सोच एक जैसी बनी हुई है कि "बस एक बार अध्यक्ष या फिर कोई पदाधिकारी बन गए तो लूट खसोट कर माल इकट्ठा करते हुए शासन-प्रशासन के लोगों से गलबहियां करने में कामयाब होंगे।" किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नही है कि क्लबिया गैंग तो गैंग ही रहेंगे। भले ही सरकारें क्यों न बदल जाएं। किसी भी प्रकार का सरकारी माल मिलेगा तो कुछेक गिने चुने ठेकेदारों को पत्रकारिता के नाम पर बने अधिकांश संगठन में चिपके पुच्छलों की सोच भी पदाधिकारी बनकर सैटिंग गैटिंग की होती है। इस लिए सबकी वफादारी सरकार व सरकारी मशीनरी के प्रति बनी रहती है।जिसके चलते उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के पत्रकारों के संगठनों से जुड़ कर संगठित रूप से सरकार व सरकारी मशीनरी की गुलामी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। करें भी क्यों ना जब एक ओर पत्रकारों को समाज में आमजन के लिए काम करते वक्त दो जून की रोटी तक नसीब नही होती। यदि कुछ मिलता भी है तो केवल अपराध में संलिप्त लोगों द्वारा ही फेंके गए टुकड़े । चोरी छिपे इन्हीं टूकडों के दम पर पत्रकारिता के लिए चलने वाली कलम और स्याही खरीदी जाती रही है। आज उन्हीं पत्रकारों के सामने सरकार तरह-तरह की योजनाएं ला रही है। लालच इंसानी फितरत है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पत्रकार ही लालच क्यों छोड़ दें? वैसे भी यह तो सरकार दे रही है। जनता से क्या मतलब? सरकार का दिया हुआ माल तो एक नंबर का माल ठहरा। पत्रकारों को बुद्धिजीवी कहा जाता है। हम भी यही सोचकर पत्रकारिता में आए थे। सोचा था कि हम बुद्धिजीवी जमात का हिस्सा होंगे। लोग तमाम बुद्धिजीवियों के साथ हमारा नाम भी लेगें। जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो हमारे सामने देश की आजादी के समय के पत्रकारों के किस्से थे। लेकिन जैसे ही हम ने पत्रकारिता शुरू की तो हमें जानकारी हुई कि पत्रकारिता तो केवल दो नम्बर के माल के बंटवारे की झट्टमझोडा मात्र है। पुराने पत्रकारों के किस्से आज भी मनमस्तिष्क को झंझोर देते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि फिर पत्रकारिता अपने असल अस्तित्व को पुनः एक बार प्राप्त कर लेगी। शायद पत्रकार लालच छोड़कर सही रास्ता अपनाने लेंगे। इसलिए हम आज भी पत्रकारिता में बने हुए हैं। हमें गर्व है कि हम देश भर के किसी भी क्लबिया गैंग के सदस्य नही है। किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार भी हम नही हैं। अब ये कहने की जरूरत बाकी नही है कि हमें सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नही चाहिए या फिर पत्रकारिता की एवज में सस्ते सरकारी मकान नही चाहिए। यहां तक कि हम तो उन सब पत्रकार संगठनों से भी इत्तफाक नही रखते जो वर्तमान में मौजूदा कानूनों और संविधान से भारतीयों को मिली अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करने के बजाए पत्रकारिता व पत्रकारों के नाम पर कुछ ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। वास्तविकता तो यह है कि पत्रकारिता के नाम पर ज्यादा पाने की इच्छा ने ही पत्रकारिता को सरकार की दरबारी पत्रकारिता में बदल दिया है।

संजय भाटी व मधु चमारी संपादक
सुप्रीम न्यूज

मुद्दा

युवाओं पर है दारोमदार

अनमोल सोवित

दुनिया में युवाओं की आबादी कुल आबादी की लगभग 16 फीसद है। यानी विश्व में 8 अरब की आबादी में लगभग 125 करोड़ युवा हैं।

युवाओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए उनके प्रतिनिधित्व की जरूरत महसूस की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए जी 20 देशों के समूह ने 20 यानी युवाओं के एक अलग समूह की स्थापना की है। जी 20 देशों के युवाओं के इस समूह की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण है। इनका योगदान न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने के क्षेत्र में है बल्कि इन युवाओं के रिसर्च और रिपोर्ट के आधार पर वैश्विक स्तर पर नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन भी जी 20 के देशों के द्वारा किया जाता रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा था 'आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वास की दृष्टि से देखती है क्योंकि भारत का जन भी युवा है, और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है, भारत अपने सपनों से भी युवा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपने चिंतन और अपनी चेतना से भी युवा है। भारत के युवाओं के पास बड़ी युवा आबादी के साथ- साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी हैं। इसका लाभ अतुलनीय है।'

युवाओं के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व को रेखांकित करने और आपसी जुड़ाव के महत्त्व को समझने की दिशा में 20 आज की तिथि में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 20 न केवल युवाओं को जी 20 के सरकार के प्रमुखों के समक्ष अपने विचारों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर देता है बल्कि यह युवाओं को कठिन बहुपक्षीय परामर्श में भी शामिल होने का मौका देता है। जी 20 शिखर सम्मेलनों के दौरान युवाओं को पर्याप्त अवसर देकर उनकी प्रतिभा और रणनीतिक एवं नेतृत्व कौशल को उभारने का प्रयास किया जाता है। जी 20 देशों ने युवाओं के कार्य कौशल एवं उनके भीतर की प्रतिभा को उभारने एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके दृष्टिकोण और वैचारिकता को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही यूथ 20 का गठन किया है। इस युवा जुड़ाव समूह में प्रत्येक जी 20 देशों के युवाओं को समान प्रतिनिधित्व मिलता है।

जिसके तहत हर देश से 5 युवाओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया जाता है। विभिन्न देशों के युवा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर एक समावेशी निर्णय पर पहुंचते हैं। तत्पश्चात अपने निर्णयों को एक रिपोर्ट के माध्यम से जी 20 के देशों के नेताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यूथ 20 के माध्यम से वैश्विक स्तर पर युवाओं को अपने राष्ट्र एवं पूरी दुनिया के भविष्य के प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है। यूथ 20 के माध्यम से युवाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने अनुभव और बुद्धिमता के द्वारा वैश्विक स्तर पर दायित्व की भावना को बढ़ावा देंगे। उनसे यह आशा होती है कि वे भविष्य के प्रति एक सकारात्मक जिम्मेदारी ग्रहण करेंगे ताकि उनके एक सुंदर और समावेशी भविष्य के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया जा सके। यूथ 20 के युवाओं को वैश्विक स्तर के सभी युवाओं की आवाज मानकर उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से बेहतर दुनिया की संकल्पना की जाती है। इंडोनेशिया में आयोजित जी 20 देशों के शिखर सम्मेलन में यूथ 20 के प्रतिनिधियों के द्वारा कई वैश्विक मुद्दों पर लंबा विचार विमर्श किया गया। युवाओं के इस समूह ने पर्यावरण, स्थिरता, शांति, सुरक्षा, समावेशन और इक्विटी के संबंध में युवाओं को दिशा दी है। युवाओं के इस अहम समूह ने वैश्विक नेताओं से सतत और रहने योग्य धरती, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार, तकनीकी विकास एवं विविधता और समावेशिता पर नीतियां बनाने का आह्वान किया है। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में संपन्न हुए जी 20 देशों के इस शिखर सम्मेलन के बाद अगले एक साल के लिए जी 20 देशों की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई। भारत वर्तमान में संसार का सबसे युवा देश है। इसलिए युआवों के लिए भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भारत इक्कसवीं सदी में दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का चतुर्दिक विकास हो रहा है।

हर क्षेत्र में भारत की हो रही इस तरक्की के आधार देश के युवा हैं। ऐसे में जी 20 की अध्यक्षता मिलने के बाद यूथ 20 के युवाओं के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी भी भारत के पास है और भारत को मिले इस अवसर का निश्चित रूप से देश के युवाओं के विकास को दिशा देगा। यूथ 20 मंच के माध्यम से भारत के युवाओं के आकांक्षाओं को प्राथमिकता देना, उनके सशक्तिकरण की जरूरत पर बल देना आवश्यक है। भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देने वाले, विश्व को नई राह दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था 'उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए।' स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरक हैं। जी 20 के मंच के माध्यम से देश के युवाओं के पास एक अवसर आया है कि अपनी क्षमता, ज्ञान और बेहतर विश्व बनाने के संकल्प के साथ एक बार पुनः विश्व का मार्गदर्शन करें।

गंगा में रासायनिक कचरा

जीवन पर संकट बनता जीवनदायी जल

पंकज चतुर्वेदी

कभी कानपुर के चमड़ा कारखाने वहां की शान हुआ करते थे, आज यही यहां के जीवन के लिए चुनौती बने हुए हैं। एक तरफ नमामि गंगे के दमकते इश्तिहार हैं तो सामने रानिया, कानपुर देहात और राखी मंडी, कानपुर नगर आदि में गंगा में अपशिष्ट के तौर पर मिलने वाले क्रोमियम की दहशत है। वह तो भला हो एनजीटी का जो क्रोमियम कचरे के निपटान के लिए सरकार को कसे हुए है। यह सरकारी अनुमान है कि इन इलाकों में गंगा किनारे सन? 1976 से अभी तक करीब 1,22,800 घन मीटर क्रोमियम कचरा एकत्र है। विदित हो क्रोमियम ग्यारह सौ सेंटीग्रेड तापमान से अधिक पर पिघलने वाली धातु है और इसका इस्तेमाल चमड़ा, इस्पात, लकड़ी और पेंट के कारखानों में होता है। यह कचरा पांच दशक से यहां के भूजल और जमीन को जहरीला बनाता रहा और सरकारें कभी जुर्माना तो कभी नोटिस देकर औपचारिकताएं पूरी करती रहीं। हालात यह हैं कि उत्तराखंड से तारणहारा के रूप में निकलती गंगा कानपुर आते-आते कराहने लगती है, सरकारी मशीनरी इसमें गंदगी रोकने के संयंत्र लगाने पर खर्चा करती है जबकि असल में इसके किनारों पर कम कचरा डालने की बात होनी चाहिए। सन? 2021 का एक शोध बताता है कि कानपुर में परमट से आगे गंगाजल अधिक जहरीला है। इसमें न सिर्फ क्रोमियम की मात्रा 200 गुना से अधिक है, बल्कि पीएच भी काफी ज्यादा है। यह जल सिर्फ मानव शरीर को नहीं बल्कि जानवरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह खुलासा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से हुई जांच में हुआ है। विभाग के छात्र और शिक्षकों ने नौ घाटों पर जाकर गंगाजल का सैंपल लिया। इनकी जांच कर टीम ने रिपोर्ट तैयार की है जो काफी चौंकाने वाली निकली है। कन्नौज के आगे गंगाजल की स्थिति बहुत अधिक भयावह नहीं है मगर परमट घाट के आगे अचानक प्रदूषण और केमिकल की स्थिति बढ़ती जा रही है। मार्च, 2022 में कानपुर के मंडल आयुक्त द्वारा गठित एक सरकारी समिति ने स्वीकार किया कि परमिया नाले से रोजाना 30 से 40 लाख लीटर, परमट नाले से 20 लाख और रानीघाट नाले से 10 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन सीधे गंगा में जा रहा है। कानपुर में गंगा किनारे कुल 18 नाले हैं जिनमें से 13 को काफी पहले टैप किए जाने का दावा किया गया है। हकीकत यह है कि ये नाले ओवरफ्लो होकर गंगा को गंदगी से भर रहे हैं। क्रोमियम की सीमा से अधिक मात्रा जाजमऊ और वाजिदपुर में भयावह हालात पैदा किये है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पानी में क्रोमियम की मात्रा 0.05 होनी चाहिए। कन्नौज से गंगा बैराज तक स्थिति लगभग सामान्य है मगर जाजमऊ और वाजिदपुर में अचानक क्रोमियम की मात्रा खतरनाक होती जा रही है। 85 गांवों के करीब पांच लाख लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। किसी परिवार में गोद सूनी है तो किसी गर्भ से उपजा नवजात मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग है। इसके अतिरिक्त भूजल में क्रोमियम की मौजूदगी ने सैकड़ों लोगों को कैंसर की सौगात बांटी है। क्रोमियम युक्त पानी ने धरती को भी बंजर किया है। इलाके में पैदावार घट गई है और फसल भी पकने से पहले मुरझाने लगती है। जाजमऊ इलाके के शेखपुर, वाजिदपुर, प्योंदी, जाना, अलौलापुर जैसे तमाम गांव है, जहां किसी महिला के गर्भ ठहरने पर खुशी से अधिक तनाव होता है। चूंकि यहां टेनरियों ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए जलशोधन के बजाय क्रोमियम युक्त पानी को सीधे गंगा नदी में बहाया है। सख्ती हुई तो अधिकांश टेनरियों ने रिवर्स बोरिंग के जरिए भूजल में प्रदूषित पानी मिलाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि गंगा के किनारे तीन-चार किलोमीटर के दायरे में भूजल में क्रोमियम की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। एक दर्जन गांवों में सरकार ने भूजल के पेयजल के रूप में प्रयोग पर रोक भी लगाई है। मजबूरी में ग्रामीण भूजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते शिशुओं के दिव्यांग पैदा होने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्नाव जनपद में गंगा कटरी में आबाद एक दर्जन गांवों में दर्जनों कैंसर रोगी हैं। जब यह पता चला कि कैंसर ग्रस्त अधिकांश लोग तम्बाकू सेवन या धूम्रपान करते ही नहीं हैं तो तीन साल पहले राज्य सरकार ने अध्ययन कराया। मालूम हुआ कि कैंसर फैलने का असल कारण भूजल में क्रोमियम है।

स्वात्वाधिकारी **मुद्रक, प्रकाशक संजय भाटी ने** वत्स आफसैट मुदद्रा हाऊस सी ब्लाक बारातघर के सामने चौडा रघुनाथपुर सेक्टर 22 नोएडा गौतमबुद्धनगर से मुद्रित एवं सेवा सदन देवला , ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित किया । RNI.NO.UPHIN/2010/33252, Mob. 9811291332 किसी भी विवाद के लिए पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी। **संपादक- मधु**

दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, राजधानी में अब रात में भी हो सकेगा पोस्टमार्टम

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब सूर्यास्त के बाद शवों का पोस्टमार्टम हो सकेगा। इससे न केवल मृतक के परिजनों के लिए स्थितियां बदलेंगी जिन्हें अकसर शव पाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, साथ ही अंगदान और प्रतिरोपण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाओं वाले अस्पतालों में रात में भी पोस्टमार्टम करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही अस्पताल इंचार्जस को सभी जरूरी इफ्रांस्ट्रक्टर पोस्टमार्टम हाउस पर सुनिश्चित करने के लिए कहा।

सिसोदिया ने कहा कि रात के समय पोस्टमार्टम होने के चलते दिल्ली में अब लोगों को शवों के पोस्टमार्टम के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे मृतकों के परिजनों को काफी सहूलियत

मिलेगी। हालांकि उन मौतों के मामले में जहां हत्या, आत्महत्या, बलात्कार या किसी तरह की गड़बड़ी का संदेह है तो शवों की जांच केवल दिन में करने का प्रावधान रखा गया है।

पोस्टमार्टम के लिए करना पड़ता था लंबा इंतजार

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। ऐसे पोस्टमार्टम उन अस्पतालों में किए जाएंगे, जिनके पास उन्हें नियमित आधार पर करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं है। अंगदान से जुड़े मामलों का पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

पहले शवों को रात के वक्त मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया जाता था। शोक संतप्त स्वजनों को शवों की अंत्येष्टि करने के लिए पूरी रात इंतजार करना पड़ता था। इससे उनकी पीड़ा और बढ़ जाती थी। पर अब रात्रि में पोस्टमार्टम हाउस पर आने वाले शवों के अंत्य परीक्षण की प्रक्रिया को मुकम्मल करने के लिए अगले दिन का इंतजार नहीं करना होगा।

पोस्टमार्टम के दौरान की जाएगी वीडियो रिकार्डिंग

सिसोदिया ने कहा कि किसी भी संदेह को दूर करने के लिए पूरी रात सभी पोस्टमार्टम के लिए वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और यह कानूनी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित रखी जाएगी। मृतक के दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा, यह नई प्रक्रिया अंगदान और प्रतिरोपण को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि प्रक्रिया के बाद निर्धारित समय में अंगों को निकाला जा सकता है।

स्टेशनों के कायाकल्प के लिए रेलवे लाया अमृत भारत स्टेशन योजना

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने 'अमृत भारत स्टेशन' योजना नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। यह दीर्घकालिक मास्टर प्लानिंग पर आधारित है। इसमें स्टेशन की जरूरतों और संरक्षण के अनुसार मास्टर प्लान के तहत कार्य होगा।

रेल मंत्रालय के अनुसार इसमें विभिन्न ग्रेड व प्रकार के प्रतीक्षालय को एक करने का प्रयास किया जाएगा और जहां तक संभव हो अच्छा कैफेटेरिया व खुदरा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म (760-840 मिलियन मीटर) उपलब्ध कराए जाएंगे। सड़कों को चौड़ा करके, अवांछित संरचनाओं को हटाकर, उचित रूप से डिज़ाइन किए गए साइनेज, समर्पित पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था आदि द्वारा सुचारू पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन के दृष्टिकोण में सुधार किया जाएगा। स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के पैमाने को व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन पर लोगों की भीड़, उपयोगकर्ताओं, विभिन्न विभागों और स्थानीय अधिकारियों सहित हितधारक परामर्श और डीआरएम की मंजूरी का भी ध्यान रखा जाएगा।

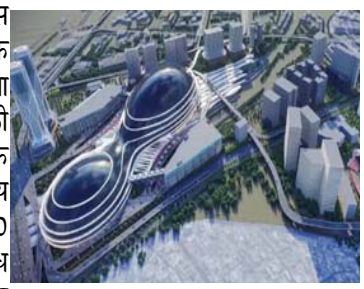

एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान बहुत प्राचीन है : डॉ संजीव सान्याल

नई दिल्ली। यह एक गलत धारणा है कि भारत का नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। भारत नाम इससे भी ज्यादा प्राचीन है। एक सभ्यतागत राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान बहुत पुरानी है। यह बात प्रसिद्ध लेखक एवं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य डॉ संजीव सान्याल ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा मंगलवार को आयोजित पद्मविभूषण डॉ कपिला वात्स्यायन स्मारक व्याख्यान में कही। डॉ संजीव सान्याल ने भारत के नामकरण और इस सभ्यता के विकास की कहानी वैदिक एवं पौराणिक ग्रंथों में मौजूद तथ्यों के आधार पर बताई। उन्होंने कहा कि भारत और सरस्वती नदी का सम्बंध बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी को अक्सर भारती भी कहा जाता है।ऋग्वेद के पैंतालीस सूक्तों में सरस्वती नदी की प्रशंसा की गई है और ऋग्वेद में 72 बार सरस्वती नदी का नाम

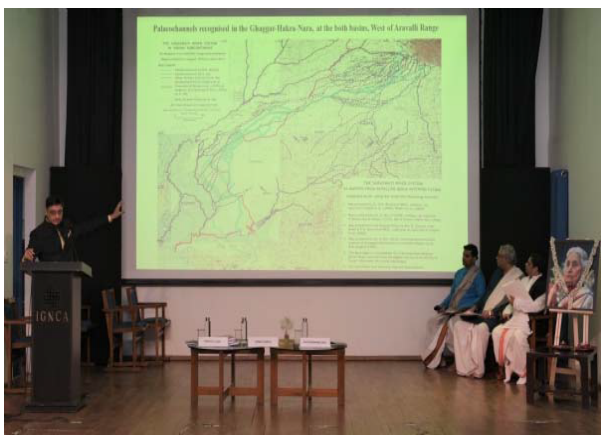

आया है। भारत के नामकरण का आधार एक वैदिक जनजाति भरत-तृत्सु थी, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करती थी। इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। डॉ संजीव सान्याल ने कहा कि एक सभ्यतागत राष्ट्र के रूप में भारत का विचार स्पष्ट रूप से बहुत प्राचीन है, लेकिन यह जड़ या कठोर नहीं है, बल्कि विकासशील है। यह व्यापार, प्रवासन (माइग्रेशन), विदेशी आक्रमणों और विचारों के आदान-प्रदान के जरिए आए विदेशी प्रभावों सहित कई नए विचारों को शामिल कर हजारों वर्षों में विकसित हुआ है।

कांग्रेस ने राजस्थान में किसी किसान की जमीन नहीं हड़पी, भाजपा ने लगाया गलत आरोप: सुरजेवाला

नई दिल्ली। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उस आरोप का खंडन किया है, जिसमें भाजपा ने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस ने किसान से जमीन छीनकर रॉबर्ट वाड्रा को दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि भाजपा के सारे आरोप आधारहीन हैं। सच तो यह है कि जमीन भाजपा के शासनकाल में हरीराम और नाथाराम को दिया गया था। उसके बाद स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदा था। बाद में राज्य सरकार ने पहली रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया। जिसके बाद जमीन को राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरे मामले में वाड्रा और 'स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी' को ही नुकसान हुआ है। सुरजेवाला ने कहा कि जमीन की बिक्री भाजपा शासनकाल में हुई थी। इस लिए इस घोटाले में भाजपा के लोग आरोपी हैं। 'स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी' और वाड्रा तो पीड़ित हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने आज एक प्रेसवार्ता के दौरान आरोप लगाया है कि राजस्थान में 2008-13 के दौरान 125 बीघा जमीन किसानों से लेकर रॉबर्ट वाड्रा को सौंपी गई। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार के लिए 'कट्टर पापी परिवार' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि परिवार का काम किसानों की जमीन हथियाना और उसे दामाद रॉबर्ट वाड्रा को सौंप देना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 125 बीघा जमीन किसानों से लेकर दो लोगों हरीराम और नाथाराम को आवंटित की गई। दोनों ही नाम फर्जी थे। इनसे यह जमीन आगे 'स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी' को बेची गई जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और

उसकी मां पार्टनर हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि हरियाणा और राजस्थान में सरकार में रहते कांग्रेस ने किसानों की जमीन हड़पी और उसे रोबर्ट वाड्रा को दी। भाजपा सरकार में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस और ईडी की जांच में पता चला कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस परिवार के आदेश पर ऐसा किया। जबकि कांग्रेस ने भाजपा के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है।

गत 8 महीनों से वेतन न मिलने के विरोध में इमामों ने वक्फ बोर्ड का किया घेराव

नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में दरियागंज स्थित दिल्ली वक्फ बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। खबर लिखे जाने तक दर्जनों इमाम वहां पर मौजूद थे और वेतन नहीं मिलने के विरोध में वक्फ बोर्ड दफ्तर पर जमे बैठे रहे। इससे पहले इमामों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा मगर सिसोदिया ने उनसे मुलाकात नहीं की। इमामों ने सिसोदिया को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें जल्द वेतन नहीं दिया गया तो वह मुख्यमंत्री आवास के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। इमामों के प्रतिनिधिमंडल

का नेतृत्व ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड कार्यालय पर मौजूद इमामों का कहना है कि उन्हें पिछले 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत दिन-प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। उनका आरोप है कि जबसे अरविंद केजरीवाल सरकार आई है तबसे उनके वेतन को लेकर के हर बार दिक्कत पेश आती है। धरना दे रहे इमामों ने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता और उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वे अपने घर नहीं जाएंगे।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसा आलिया, मस्जिद फतेहपुरी के स्टाफ को भी पिछले दो साल से वेतन नहीं मिला है। यहां के शिक्षक भी इमामों के साथ बोर्ड का घेराव कर रहे हैं। धरनारत शिक्षक मौलाना अबरार अहमद ने बताया कि उन्हें पिछले 2 सालों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री से भी की गई मगर कोई हल नहीं निकला। उनका कहना है कि इतने दिनों तक वेतन नहीं मिलने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि इमामों को वेतन नहीं मिलने से उनको काफी परेशानियों का सामना है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह मुख्यमंत्री आवास के बाहर भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे।

विकास दुबे के भाई और बहनोई को सजा

कानपुर देहात,। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे,उसके भाई अविनाश दुबे,दीपू दुबे व बहनोई दिनेश तिवारी पर 21 साल पहले दर्ज हुए एक गैंगस्टर के मुकदमे में पांच साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। विकास दुबे व उसका भाई अविनाश दुबे की मौत हो चुकी है और वही विकास का दूसरा भाई दीपू दुबे लखनऊ जेल में बंद है। बहनोई दिनेश तिवारी को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है। न्याय विभाग के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि कानपुर देहात के शिवली में पूर्व प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर पांडेय की हत्या और बलवे के मामलों में आरोपित होने के बाद शिवली पुलिस ने 2001 में विकास दुबे, उसके भाइयों दीपू दुबे व अविनाश दुबे और बसेन निवासी उसके बहनोई दिनेश तिवारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। सुनवाई मौजूदा समय में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में चल रही थी जो 21 दिसंबर को पूरी हो गई और कोर्ट ने दोनों ही पक्ष की जिरह सुनने के बाद गुरूवार को गैंगस्टर एक्ट में सभी आरोपियों को पांच साल की सजा के साथ पांच हजार का जुमार्ना लगाते हुए फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि 2001 में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है।सुनवाई के दौरान विकास व अविनाश की मौत होने के कारण उनकी फाइल अलग कर दी गई थी। दीपू दुबे सामूहिक हत्याकांड में पहले से ही लखनऊ जेल में बंद है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दीपू दुबे और बहनोई दिनेश तिवारी को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

उप्र : युवक ने चचेरे भाई की हत्या की, मामला दर्ज

बुलंदशहर,। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की कथित तौर पर फावड़े से मारकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। शिकारपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) वरुण कुमार सिंह ने बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के बसौटी गांव में बृहस्पतिवार रात मनोज (25) नामक एक युवक की उसके चचेरे भाई ने फावड़े से मारकर हत्या कर दी। सिंह के मुताबिक, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन की जा रही है। सीओ ने बताया कि आरोपी घटना के बाद फरार हो गया, लेकिन उसे जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात की तहकीकात की जा रही है कि घटना के पीछे की वजह क्या है।

पांच अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, एक करोड़ 40 लाख रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद

सोनभद्र (उप्र),। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के म्योरपुर में एक करोड़ 40 लाख रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद कर दो महिलाओं समेत पांच अंतर्राज्यीय तस्करों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्र ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार की शाम म्योरपुर क्षेत्र में पुलिस, स्वाट टीम एवं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने संयुक्त कार्यवाही में रन टोला तिराहे पर एक कार, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल को रोककर दो महिलाओं और तीन पुरुषों की तलाशी ली, तो उनके पास से एक किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ 40 लाख रुपये बतायी गई। पुलिस ने हीरोइन बरामदगी के बाद मीरा देवी, मनीषा सिंह, विजय पटेल, जितेंद्र नाथ तथा सुरेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ़्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे बाराबंकी से हेरोइन लेकर आते हैं और सोनभद्र के बभनी, म्योरपुर, रेणुकूट, शक्तिनगर और अनपरा में बेचते हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध एन डी पी एस अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में भेज दिया है।

भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी दलों का किनारा:जयंत 9 दिन के लिए बाहर गए; सपा बोली- अखिलेश के पास टाइम नहीं

उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता दिया है। इसमें प्रमुख रूप से अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, राकेश टिकैत के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इनमें से कई नेताओं ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही इससे किनारा कर लिया है। इधर, इस यात्रा के यूपी कोऑर्डिनेटर सलमान खुर्शीद का कहना है कि हम तब तक आधिकारिक रूप से नाम नहीं बताएंगे, जब तक संबंधित के पास हमारा आमंत्रण पत्र नहीं पहुंच जाता। क्योंकि अगर हम नाम सार्वजनिक कर दें और संबंधित तक आमंत्रण पत्र ही नहीं पहुंचे तो फिर तरह-तरह की बातें बनती हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जयंत के निजी सहायक समरपाल सिंह ने 'दैनिक भास्कर' से फोन पर कहा, 'जयंत चौधरी 27 दिसंबर को बाहर चले गए हैं और 4 जनवरी को लौटेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का न्योता मिला है, लेकिन उनका प्रोग्राम पहले से तय है। इसलिए वह इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे।' भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 'भारत जोड़ो यात्रा का न्योता मिला है। तभी कुछ फाइनल हो पाएगा। हालांकि राहुल गांधी बढ़िया काम कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण में उनका सबसे बड़ा रोल रहा था। आज जिस किसान को जमीन-जायदाद से दो रुपए भी आमदनी हो रही है, वो राहुल की देन है।' भारत जोड़ो यात्रा का आमंत्रण मिला या नहीं? इस सवाल पर सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, 'हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी के ही इतने कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इस यात्रा में जाएंगे।' बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि बहन मायावती को न्योता मिला या नहीं। इस बारे में वही बता सकती हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और मैं सर्वसमाज जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूं। अयोध्या से यह यात्रा शुरू हो चुकी है। हर मंडल में रोजाना कार्यक्रम हो रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा से हमें कोई मतलब नहीं है।' करीब 2800 किलोमीटर का सफर करके भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली में आकर 26 दिसंबर को ब्रेक लिया है। ये यात्रा अब 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से शुरू होगी। 3 जनवरी को गाजियाबाद, 4 जनवरी को बागपत और 5 जनवरी को ये यात्रा शामली में होगी। इसके बाद ये कैराना के रास्ते हरियाणा के पानीपत बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। यूपी में इसका रूट करीब 130 किलोमीटर रहेगा। इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिमी यूपी में डेरा डाल दिया है और हर रोज बैठकें कर रहे हैं।

नए साल के जश्न पर होगा 200 करोड़ का बिजनेस:इसके लिए नोएडा में पब-बार और डिस्को का कॉकटेल हो चुका है तैयार

नोएडा । नोएडा में नए साल के जश्न को लेकर नोएडा में तैयारी पूरी हो चुकी है। पब और बार में डिनर, डांस के साथ कॉकटेल का त्रिपल मजा मिलेगा। ज्यादातर पब-बार में कपल एंट्री है। जिनकी बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है। इसमें अधिकांश के टिकट बिक चुके है। कुछ पब और बार के टिकट बचे है। वहीं रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व कराई जा रही है। हालांकि अधिकांश रेस्टोरेंट स्पाट रिजर्वेशन ही करेंगे। बताया गया कि कोरोना पाबंदी हटने के बाद ये पहला मौका होगा जिसमें जश्न का मजा दोगुना होगा। हालांकि नए वैरियंट के दस्तक देने के साथ ही पब बार और रेस्टोरेंट मालिक सावधानी रखेंगे। इसलिए टिकट के साथ उन्हें कोविड प्रोटोकॉल मानने की सलाह भी दी जा रही है। वहीं रेस्टोरेंट से लेकर पब बार में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ऐसा बताया गया है। इस बार महज 31 दिसंबर की नाइट को ही नोएडा में करीब 150 से 200 करोड़ रुपए का बिजनेस होने की आशंका है। इस पेशे से जुड़े लोगों का कहना है कोरोना पाबंदी कम होने की वजह से लोगों में 32 नाइट का क्रेज ज्यादा है। ऐसे में बुकिंग अमाउंट भी इसी लिहाज से रखे गए है। नोएडा में कपल एंट्री 31 की नाइट 2500 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक है। हालांकि सोलो एंट्री नहीं है। आकलन लगाया जा रहा है कि 31 दिसंबर को बड़े-बड़े पब और बार में एक रात में 30 लाख रुपए प्रति बार तक की शराब परोसी जा सकती है। अधिकांश नाइट कार्यक्रम सुबह 1 बजे और 2 बजे तक चलेंगे। इसके लिए पब और बार अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे है। हालांकि बाउंसर को नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस हेल्पलाइन नंबर और नजदीकी थाने की पुलिस से संपर्क रहेगा। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के नोएडा प्रैजिडेंट वरुण खेड़ा ने बताया कि इस बार कम से कम 150 से 200 करोड़ का बिजनेस होगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नोएडा में करीब 200 रेस्टोरेंट और करीब 100 से ज्यादा बार पब है। इनकी अपनी वेबसाइट और और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म से बुकिंग की जा रही है।

गाजियाबाद में छात्र गुटों में चले लाठी-डंडे और बेल्ट:बाइक की साइड लगने पर हुआ था विवाद, सड़क पर मची अफरा-तफरी

गाजियाबाद । गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में स्कूल की छुट्टी के बाद दो छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई। लाठी-डंडे चले और छात्रों ने एक-दूसरे पर बेल्ट बरसाईं। एक छात्र से बाइक की साइड लगने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए छात्रों की पहचान शुरू कर दी है। अउढ पूनम मिश्रा ने बताया, 'अर्थला मेट्रो स्टेशन के बाहर सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच मारपीट की एक वीडियो वायरल हो रही है। साहिबाबाद पुलिस ने इस संबंध में मौके पर जाकर जांच-पड़ताल की है। वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की गई है। इस मामले में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।' मारपीट करने वाले बच्चे साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला स्थित कैलाशवती सरकारी स्कूल के थे। मंगलवार दोपहर इस स्कूल की छुट्टी करीब तीन बजे हुई। इसके बाद छात्र-छात्रा समूह में घर लौट रहे थे। इस दौरान बाइक एक छात्र से टकरा गई। इसी से विवाद शुरू हुआ और नौबत मारपीट तक आ गई। बस फिर क्या, छात्रों के दो समूह भिड़ गए। खूब लाठी-डंडे और बेल्ट चलीं। एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ाकर सड़क पर पीटा गया। छात्रों का मामला होने की वजह से अन्य किसी ने बीच-बचाव की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों ने बताया कि छात्राओं से छेड़छाड़ हुई थी, जिसे लेकर दो छात्र गुटों में मारपीट हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि छेड़छाड़ जैसा कोई मामला नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस स्कूल के छात्र आए दिन इस तरह मारपीट करते रहते हैं। इससे स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है।